रजिस्टर्ड न 0 पी 0/एस 0 एम 0 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(भसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 1 सितम्बर, 1988/10 भाइपद, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 1st September, 1988

No. 1-39/88-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, "The Himachal Pradesh Legislative

Assembly (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Bill, 1988 (Bill No. 10 of 1988)" having been introduced on the 1st September, 1988 in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH, Secretary.

1988 का विधेयक संख्यांक 10

्हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भन्ते और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते ग्रौर पेन्शन) ग्रिधिनियम, 1971 (1971 का 8) में ग्रौर संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह श्रिधिनियमित हो :—

1. इस ग्रधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भन्ते ग्रौर पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) ग्रधिनियम, 1988 है। संक्षिप्त नाम

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) ग्रिधिनियम, धारा 4 का 1971 की धारा 4 में शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर, जहां भी यह ग्राया है, "एक सौ" संशोधन। शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों श्रीर कारणों का कथन

मूल्यों में ग्रत्यधिक वृद्धि के कारण यह युक्तियुक्त समझा गया है कि विधायकों को प्रतुज्ञेय विराम/ दैनिक भत्ते को 75/- रुपए से बढ़ा कर 100/- रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए ।

विधेयक उपर्यक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

णिमला : 1 सितम्बर, 1988 वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

अस्तावित विधेयक के खण्ड 2 के भ्रधिनियमित होने पर, भ्रासीन विधायकों को भ्रनुजैय विराम/दैनिक भत्ते को पचहत्तर रुपए से एक सौ रुपए प्रति दिन करने पर प्रतिवर्ष, तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए का भ्रतिरिक्त भ्रावर्ती व्यय भ्रन्तिविलित होगा । :

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-श्रय-

भारत के संविधान के प्रनुक्छंद 207 के प्रधीन राज्यवाल की सिकारिश

[संचिका सं0 जी0 ए0 डी0 (पी0 ए0) 4 (डी)-17/88]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (दितीय संशोधन) विधेयक, 1988 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के प्रधीन उक्त विधंयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

(Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Sadasyon ke Bhatte aur Pension) (Dvitiya Sanshodhan) Vidheyak, 1988 (1988 ka Vidheyak Sankhyank 10) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

Bill No. 10 of 1988.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (SECOND AMENDMENT) BILL, 1988

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

of 1971

- 1. This Act may called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Short title (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Act, 1988.
- 2. For the word "seventy-five" wherever it occurs in section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, the words "one hundred" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the steep rise in prices, it has been considered reasonable that halting/daily allowance, as is admissible to the Legislators, be increased from Rs. 75/- to Rs. 100/- per day.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective: .

SHIMLA:

The 1st September, 1988.

VIRBHADRA SINGH, Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the proposed Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of Rs. 3.75 lakh per annum on account of the increase in the halting/daily allowance admissible to sitting M.L.As. from Rs. 75/- to Rs. 100/- per day.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. GAD(PA)-4(D)-17/88]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Bill. 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.